

हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लयि गए महत्त्वपूर्ण नरिणय

चर्चा में क्यौं?

21 जुलाई, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड द्वारा डबिंचर/ऋण की फ्लोटेशन के लयि एक हजार करोड़ रुपए की ब्लॉक गारंटी के नवीनीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

प्रमुख बदि

- हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड ने नाबार्ड से डबिंचर/ऋण की फ्लोटेशन के लयि राज्य सरकार की एक हजार करोड़ रुपए की गारंटी को सात साल, यानी 1 मार्च, 2022 से 31 मार्च, 2029 तक के लयि रनियू करने का प्रस्ताव पेश किया था।
- हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड को हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के तहत स्थापति किया गया था।
- यह सहकारी संस्था प्रदेश में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के विकास हेतु किसानों को दीर्घकालीन ऋण नविश उपलब्ध कराने में लगी है। इस तरह की क्रेडिट सीमा/ऋणों के लयि उन्हें नाबार्ड के डबिंचर/ऋण पर नरिभर रहना पड़ता है। नाबार्ड सरकारी गारंटी पर यह सुविधा प्रदान करता है।
- इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कर्मचारी आचरण नयिमावली, 2016 के नयिम 24 में संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
- संशोधन के अनुसार, 'आचरण नयिम, 2016' के नयिम 24 में वर्णति चल संपत्ति की परिभाषा में 'बीमा नीतियौं' शब्द हटा दिया गया है। इसी प्रकार, अनुलग्नक-ए में 'बीमा नीतियौं' शब्द जहाँ कहीं भी आएं, उन्हें हटा दिया गया है।
- राज्य सरकार ने 'चल संपत्ति' की परिभाषा में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार किया और 'आचरण नयिम, 2016' के नयिम 24 में वर्णति 'चल संपत्ति' की परिभाषा में संशोधन करने का नरिणय लिया।
- चल संपत्ति के स्पष्टीकरण में उल्लिखित सभी वस्तुओं को एक कर्मचारी द्वारा खुले बाजार में स्थानांतरित/बेचा जा सकता है, लेकिन 'बीमा नीतियौं' किसी अन्य व्यक्ति या पार्टी को बेची/हस्तांतरण नहीं की जा सकती हैं। इसलिये, केवल 'चल संपत्ति' की अभिव्यक्ति से 'बीमा नीतियौं' शब्द को हटाने का नरिणय लिया गया।